vkj- ,u- vkb- u- UPHIN/2010/32566 Mkd- ith;u- l[;k& SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक
हर ख़बर पर पैनी नज़र

o"k Z % 16 vad % 20 y[kuÅ] x:okj 28 vxLr 2025 l 06 fl rEcj 2025 rd i"B&8 eY; % ,d :i;k

भारत का गोवा बनेगा शतरंज की नई राजधानी! भारत करेगा फिडे विश्व कप २०२५ की मेजबानी

नई दिल्ली। FIDE विश्व कप २०२५ गोवा आ रहा है! ३० अक्टूबर से २७ नवंबर, २०२५ तक, दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी भारत के पश्चिमी तट पर शतरंज के सबसे रोमांचक आयोजनों में से एक के लिए एकत्रित होंगे। इस न कआउट मुकाबले में २०६ खिलाड़ी २०,००,००० अमेरिकी डॉलर की राशि और २०२६ के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में तीन प्रतिष्ठित स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। हर राउंड जीतो या घर जाओ वाला है, जिससे यह विश्व कप कैलेंडर के सबसे रोमांचक टूर्नामेंटों में से एक बन गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि दो दशक से अधिक समय के बाद प्रतिष्ठित फिडे विश्व कप २०२५ की मेजबानी करना भारत के लिए प्रसन्नता की बात है। मोदी ने कहा कि शतरंज युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस टूर्नामेंट में रोमांचक मैच देखने को मिलेंगे और दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, ''प्रतिष्ठित फिडे विश्व कप २०२५ की मेजबानी करना भारत के लिए प्रसन्नता की बात है और वह भी दो दशक से अधिक समय के बाद।'' फिडे शतरंज विश्व कप का आयोजन गोवा में ३० अक्टूबर से २७ नवंबर

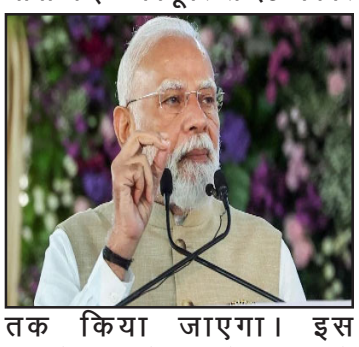

तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में अगले साल के कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए तीन स्थान और २० लाख डॉलर की इनामी राशि दांव पर लगी होगी। इस टूर्नामेंट में विश्व चौंपियन डी गुकेश, मैग्नस कार्लसन, फाबियानो करुआना और आर प्रज्ञानानंदा सहित २०६ खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। गोवा के शानदार समुद्र तट, जीवंत संसेंति और गर्मजोशी भरा आतिथ्य इसे इस वैश्विक मुकाबले के लिए एक रोमांचक पृष्ठभूमि बनाते हैं। खिलाड़ी और प्रशंसक विश्वस्तरीय शतरंज का अनुभव करेंगे, साथ ही अपनी ऊर्जा और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध इस जगह का भी। भारत का शतरंज से गहरा नाता है, और हाल के वर्षों में यह देश एक वैश्विक शक्ति बन गया है, जिसने शीर्ष खिलाड़ी दिए हैं और महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों की मेजबानी की है। पिछले साल, गुकेश डोमाराजू विश्व चौंपियन बने, जबकि भारतीय टीमों ने ओपन और महिला दोनों वर्गों में शतरंज ओलंपियाड जीता। यह सिलसिला जारी रहाः इस जुलाई में, महिला विश्व कप में दिव्या देशमुख ने शानदार प्रदर्शन किया, जिन्होंने ट्रॉफी उठाकर दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। गोवा में ओपन विश्व कप का आयोजन इन सफलताओं को और बढ़ाता है और स्थानीय प्रशंसकों को अपने सितारों को घरेलू धरती पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते देखने का अवसर प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश कभी बीमारू नहीं था, वंशवाद-भ्रष्टाचार ने डुबोया था : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश मूलतः 'बीमारू' राज्य नहीं था, बल्कि भ्रष्ट राजनीतिक दलों, वंशवाद और नियुक्तियों में पक्षपात के कारण पतन की ओर धकेला गया था। वह लोक भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहाँ यूपीएसएसएससी की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चयनित २,४२५ महिला पर्यवेक्षकों और १३ फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए योगी ने कहा कि १९४७ से १९६० तक, उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक था, जिसका राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में १४ प्रतिशत से अधिक का योगदान था। उन्होंने कहा कि यह गिरावट १९६० के बाद शुरू हुई और १९९० के बाद और तेज हो गई। २०१७ तक, उत्तर प्रदेश का हिस्सा ८ प्रतिशत से भी कम रह गया था। उन्होंने आगे कहा कि राज्य भ्रष्टाचार, दंगों और उपेक्षा से ग्रस्त था, जिसके कारण युवाओं को पलायन करना पड़ा और उन्हें बाहर भी पहचान के संकट से जूझना पड़ा। सरकार के पारदर्शी भर्ती अभियान पर प्रकाश डालते हुए, योगी ने कहा कि अब दूरदराज और आदिवासी इलाकों के योग्य युवाओं तक अवसर पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर युवा के सपने होते हैं, लेकिन जब वे भेदभाव का शिकार होते हैं, तो यह राष्ट्रीय क्षति है। आज की निष्पक्ष नियुक्तियाँ साबित करती हैं कि प्रतिभा हर जगह हैंबस उसे अवसर की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षकों और फार्मासिस्टों को बधाई दी और पोषण एवं बाल कल्याण सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र २०४७ के

विकासशील भारत की नींव होंगे और इस बात पर जोर दिया कि एक स्वस्थ बचपन एक समृद्ध भविष्य का निर्माण करता है। उन्होंने नियुक्त लोगों से ईमानदारी और बिना किसी भेदभाव के सेवा करने का आग्रह किया और उनकी भूमिका की तुलना 'भगवान कृष्ण का पालन–पोषण करने वाली माता यशोदा' से की। स्कूलों के विलय की विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए, योगी ने कहा कि जीर्ण–शीर्ण स्कूलों का स्थानांतरण और छात्र–शिक्षक अनुपात में सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। उन्होंने आगे कहा, 'खाली पड़े स्कूलों में बाल वाटिका और प्री–प्राइमरी कक्षाएँ संचालित की जाएँगी, जिससे बच्चों के लिए सुरक्षित और आधुनिक सुविधाएँ सुनिश्चित होंगी।'

योगी ने बाढ़ के खतरे के मद्देनजर अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ के आसन्न खतरे को देखते हुए मंगलवार को अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि एक बार फिर पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का पानी बढ़ने लगा है। ऐसे में योगी ने तत्काल मामले की गंभीरता को भांपते हुए अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। योगी ने अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हुए कहा कि " कोई भी व्यक्ति बाढ़ की समस्या से परेशान न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किये जाएं। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर तत्काल पहुंचाया जाए। साथ ही उनकी हर एक आवश्यकता को पूरा किया जाए।" उन्होंने अधिकारियों को मवेशियों के लिए भी विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिये हैं। राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि

वर्तमान में प्रदेश के २२ जिलों की ४३ तहसीलें और ७६८ गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों में बाढ़ से २,५२,८३६ लोग प्रभावित हैं, जिन्हें राहत सहायता प्रदान की गयी है। वहीं, बाढ़ की वजह से ३३,३७० मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। बाढ़ से किसी परिवार के मकान को क्षति नहीं पहुंची है। प्रदेश में ३७,२७६ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल बाढ़ की चपेट में आया है। इन प्रभावित क्षेत्रों में ५५० नावों और मोटरबोट की सहायता से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इन इलाकों में मंगलवार को भोजन के ६,४५८ पैकेट और ७,१४३ लंच पैकेट वितरित किये जा चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश के २२ जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें वाराणसी, प्रयागराज, औरैया, बहराइच, बांदा, मिर्जापुर, कानपुर देहात, चंदौली, फतेहपुर, कानपुर नगर, बाराबंकी, बदायूं, फर्रुखाबाद, गोंडा, हरदोई, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फनगर, शाह जहांपुर और उन्नाव शामिल हैं। इन सभी जिलों में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं।

रसायन कारखाने में आग लगने से चार मजदूर गंभीर रूप से झुलसे

अमेठी। अमेठी जिले के कमरौली थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक रसायन कारखाने में मंगलवार दोपहर बाद भीषण आग लगने से चार मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक कारखाने में सामान्य रूप से काम चल रहा था, तभी अचानक आग लगने से वहां अफरा–तफरी मच गयी। चार मजदूर इसकी चपेट में आकर झुलस गए। सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

मुसाफिरखाना के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि आग की चपेट में आने से जयप्रकाश (५०) निवासी ब्यौरेमऊ शुक्ल बाजार, अशोक (४८) और राम अवध (५२)निवासी ढूंढेहरी तथा संतोष (५०) निवासी रोड नंबर चार गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) जगदीशपुर में भर्ती कराया गया है।

सम्पादकीय

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नया रणक्षेत्र

तीस दिन से ज्यादा जेल में बंद नेताओं को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पद से हटाने से संबंधित विधेयक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नया रणक्षेत्र है। चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है, जिसे पारित कराने के लिए दो तिहाई सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा और ये समर्थन सत्ताधारी एनडीए के पास नहीं है, तो केंद्र ने विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बनाने का निर्णय लिया। लेकिन विपक्ष इससे आश्वस्त नहीं हुआ है। अब तक चार पार्टियां जेपीसी में शामिल ना होने की बात कह चुकी हैं। इनमें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और दूसरे एवं तीसरे नंबर की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियां– सपा और तृणमूल कांग्रेस शामिल हैं। उनके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी जेपीसी से अलग रहने का एलान किया है। संभावना है कि ऐसा ही रुख कुछ अन्य दल भी अपनाएंगे। तो कुल मिलाकर संबंधित विधेयक को संसदीय साख दिलाने और इस बीच दो तिहाई बहुमत का इंतजाम करने की सत्ता पक्ष की रणनीति कारगर होती नहीं दिखती। विपक्षी दलों ने दो–टूक कहा है कि इस विधेयक का निशाना गैर–भाजपा पदाधिकारी बनेंगे। यह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ते अविश्वास का संकेत है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से ही तलवारें खिची हुई हैं। दोनों के बीच चौड़ी होती खाई के पीछे और भी कई मुद्दे हैं। यानी संसदीय लोकतंत्र की बहस–मुबाहिशे से मसलों को हल कर लेने की विशेषता भारत में चूक रही है। विपक्ष की निगाह में सत्ता पक्ष सिर्फ अपनी नीतियों को लागू करने के क्रम में ही असहमति को नजरअंदाज नहीं कर रहा, बल्कि वह पूरे सत्ता तंत्र पर कब्जा करने की ओर बढ़ रहा है। यह तानाशाही का रास्ता है। यानी आरोप है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सत्ता में आने के बाद वर्तमान सत्ताधारी दल की मंशा लोकतंत्र को महज औपचारिक बना देने की है। इसलिए सत्ता पक्ष से सहयोग की गुंजाइश नहीं है। क्या बनती गई इस स्थिति का यह संदेश नहीं है कि वर्तमान व्यवस्था में भरोसा बरकरार रखते हुए मतभेदों को हल करने की गुंजाइश अब बेहद सिकुड़ गई है?

कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड के दोषी सलीम की इलाज के दौरान मौत

लखनऊ। कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी सलीम की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। लखनऊ जिला कारागार के जेलर ने सलीम की मौत की पुष्टि की है। सलीम को इलाज के लिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में भर्ती कराया गया

था, जहां पुलिस सुरक्षा में उसका इलाज चल रहा था। बुधवार को उसकी हालत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। सलीम, २०१८ में कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में मारे गए चंदन गुप्ता की हत्या का शामिल था। एनआईए स्पेशल कोर्ट, लखनऊ ने सलीम को अन्य २७ दोषियों के साथ इस मामले में दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट का फैसला आने के बाद सलीम ने अन्य दोषियों के साथ आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद से वह जेल में बंद था। गौरतलब है कि कासगंज में २६ जनवरी २०१८ को तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और अन्य साथियों के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल था। जब तिरंगा यात्रा कासगंज के तहसील रोड स्थित जीजीआईसी गेट के पास पहुंची, उसी दौरान विवाद हुआ। आरोप थे कि सलीम, वसीम और नसीम समेत कई लोगों ने रास्ता रोक लिया। जब चंदन ने आपत्ति जताई तो इससे हालात बिगड़ गए और पथराव होने लगा। तिरंगा यात्रा के दौरान गोलीबारी की भी घटना हुई। मुख्य आरोपियों में से एक, सलीम ने चंदन गुप्ता पर गोली चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। हिंसा के कारण शहर में अशांति फैल गई, जिसके कारण एक सप्ताह तक कर्फ्यू लगा रहा और इंटरनेट बंद रहा। मामले में करीब ६ साल की कानूनी लड़ाई के बाद चंदन के परिवार को जनवरी २०२५ में न्याय मिला। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में २८ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दो लोगों को इस मामले से बरी भी कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे।

सीएम योगी ने किया 'रोजगार महाकुंभ 2025' का शुभारंभ

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कार्य करने वाले प्रत्येक युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। कोई भी कंपनी या नियुक्ता कर्मचारी का शोषण नहीं कर पाएगा। नियुक्ति देने वाली कंपनियां अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेंगी, जबकि इसके अतिरिक्त चार्जेज की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यह व्यवस्था युवाओं को सम्मानजनक रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित तीन दिवसीय 'रोजगार महाकुंभ २०२५' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है, जहां काम करने वाले हर युवा को न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम वेतन की गारंटी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को अपार ऊर्जा का स्रोत बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी युवा आबादी इस राज्य के लिए सौभाग्य है। आज यूपी की प्रतिभाओं की मांग देश–दुनिया में हो रही है और जो प्रदेश कभी रोजगार के लिए पलायन का दंश झेलता था, आज वही रोजगार उपलब्ध करा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि कभी पूरा–का–पूरा गांव रोजगार के लिए प्रदेश छोड़कर पलायन करता था, लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश अपने भीतर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। यह परिवर्तन बीते ८ वर्षों में हुए सुनियोजित प्रयासों का परिणाम है। आज यूपी की प्रतिभा दुनिया भर में प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन रोजगार और विकसित भारत के संकल्प का हिस्सा है। हर युवा को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलना जरूरी है। जहां अवसर मिला, वहां इन युवाओं ने अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य से लोहा मनवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) योजना के जरिए परंपरागत उद्यमों को नई पहचान दी गई है। एमएसएमई सेक्टर में ६६ लाख यूनिट पुनर्जीवित हुए हैं। कोरोना काल में जब ४० लाख से अधिक प्रवासी कामगार लौटे, तब इन्हीं एमएसएमई यूनिट्स ने ६० प्रतिशत को रोजगार दिया, और वे आज भी उसी व्यवस्था से जुड़े हैं। सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने एमएसएमई यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उद्यमियों

को ५ लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर उपलब्ध कराया है। यदि प्रत्येक यूनिट २ से १० युवाओं को रोजगार दे रही है, तो लाखों–करोड़ों लोग प्रदेश में सम्मानजनक काम पा रहे हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार कर रहा है। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि परंपरागत कारीगरों और हस्तशिल्पियों को सम्मान देने के लिए 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान' और 'पीएम विश्वकर्मा' योजनाएं लागू की गई हैं। बढ़ई, राजमिस्त्री, लोहार, सोनार, कुम्हार, मोची, नाई जैसे परंपरागत कामगारों को मुफ्त टूलकिट, सस्ता ऋण और ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके जरिए लाखों लोगों को रोजगार और सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि २४ जनवरी २०२५ को शुरू हुई 'सीएम युवा उद्यमी स्कीम' के तहत २१ से ४० वर्ष तक के युवाओं को बिना गारंटी ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें किसी भी युवा की उसकी जाति उसका मत उसका मजहब उसका चेहरा देखकर के नहीं बल्कि उसकी रुचि के अनुसार उसे यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अब तक ७०,००० से अधिक युवाओं ने इस स्कीम से जुड़कर अपने उद्यम स्थापित किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि बीते ८ वर्षों में पारदर्शिता के साथ ८.५ लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसमें पुलिस विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पीडब्ल्यूडी और विश्वविद्यालयों में भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हैं। इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाले देश के अंदर सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती आती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के चलते प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बना है। पिछले ८ वर्षों में ३३ से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसी लागू की गईं। इन्वेस्ट यूपी पोर्टल, निवेश मित्र और सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के जरिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई। परिणामस्वरूप १५ लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश जमीनी स्तर पर उतरे हैं और ६० लाख युवाओं को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन और स्किल डेवलपमेंट मिशन के जरिए युवाओं को नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोल जी, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। टाटा टेक्नोल जी के सहयोग से आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में नई लैब और कोर्स शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विदेश जाने वाले युवाओं को भाषा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जर्मनी जाने वालों को जर्मन भाषा, जापान जाने वालों को जापानी और अन्य देशों में जाने वालों को उनकी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वहां पहुंचने के बाद युवाओं को प्रशिक्षण या भाषा की वजह से कठिनाई न झेलनी पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि हर टेक्नोलॉजी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वह समय के अनुरूप बदलती है हमें समाज के मांग के अनुरूप अपने आप को अपडेट करना होगा।

वायु सेना के सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार से 3.21 करोड़ रुपये की ठगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नोएडा में साइबर अपराधियों ने वायुसेना के सेवानिवृत्त कर्मचारी को पत्नी और बेटी समेत ३६ दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर उनसे ३.२१ करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक जालसाजों ने पीड़ित परिवार को धनशोधन मामले में आरोपी बताकर खुद को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा का अधिकारी बताया और उन्हें गिरफ्तारी का भय दिखाकर ठगी कर ली। पुलिस उपायुक्त

(साइबर अपराध) प्रीति यादव ने बताया कि सेक्टर–२५ स्थित जलवायु विहार में रहने वाली मलोबिका मित्रा ने मंगलवार को साइबर अपराध थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके पिता सुबीर मित्रा को १८ जुलाई को अज्ञात नंबर से कॉल आई थी। मलोबिका ने बताया कि पिता सुबीर मित्रा वायुसेना से सेवानिवृत्त हैं तथा वह पिता और मां केया मित्रा के साथ रहती हैं। उन्होंने बताया कि जालसाजों ने खुद को ट्राई का कर्मचारी बताया। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

उप्र में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत, बेखौफ यात्रा कर सकती हैं बेटियां : राज्यपाल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को कहा कि पहले राज्यमें बेटियां शाम पांच बजे के बाद बाहर निकलने से डरती थीं, लेकिन आज कानून–व्यवस्था के मजबूत ढांचे के कारण आधी रात को भी बेखौफ यात्रा कर सकती हैं। पटेल ने मंगलवार को गोरखपुर जिले में स्थित २६वीं पीएसी बटालियन, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। कैंटीन आदि का निरीक्षण करने के बाद, उन्होंने प्रशिक्षु महिला कांस्टेबल से बातचीत की। उत्तर प्रदेश राजभवन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि महिला कांस्टेबल ने राज्यपाल के साथ अपने अनुभव साझा किए। राज्यपाल ने महिला पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, ''

उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है, जिसमें ७५ जनपद और २५ करोड़ से अधिक की जनसंख्या है। इन सभी की सुरक्षा और कानून–व्यवस्था बनाए रखना आप सबकी जिम्मेदारी होगी।'' राज्यपाल ने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य सुरक्षा प्रबंधन सीखना, विभिन्न परिस्थितियों में कानून–व्यवस्था बनाए रखना और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित करना है। यही शिक्षा आगे चलकर प्रदेश व समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि सभी के लिए कानून समान है और जो व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है, उसके लिए दंड निश्चित है। जब कानून का कड़ाई से पालन होता है, तभी समाज में शांति स्थापित होती है। पटेल ने निर्देश दिए कि प्रशिक्षण के दौरान महिला कांस्टेबलों का बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) नियमित रूप से जांचा जाए और शरीर की आवश्यकता के अनुसार उन्हें संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाए।

अपर नगर आयुक्त ने कर्मचारियों की मांग पूरी करने का दिया आश्वासन

लखनऊ। नगर निगम एवं जलकल कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने आज अपर नगर आयुक्त नम्रता सिंह के साथ बैठक की। इस दौरान कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की १७ सूत्रीय मांगों को रखा, साथ ही इन मांगों के पूरा न होने से कर्मचारियों को हो रही समस्याओं की भी जानकारी अपर नगर आयुक्त को दी। जिसके बाद अपर नगर आयुक्त ने कर्मचारियों की मांगों पर जल्द निर्णय होने का आश्वासन दिया है। नगर निगम एवं जलकल कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने बताया कि आज की बैठक में नगर निगम एवं जलकल कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी व अन्य लाभ दिये जाने सम्बन्धी लम्बित मांगो पर अपर नगर आयुक्त से वार्ता हुई, जिस पर अपर नगर आयुक्त ने बहुत ही सकारात्मक निर्णय लिये जाने का आश्वासन दिया। संघ द्वारा पूर्व में नगर आयुक्त के साथ २७ सितम्बर, २०२४ को हुई बैठक की कार्यवृत्त की भी जानकारी दी, साथ ही उसके अनुपालन में आज तक कोई कार्रवाई न किये जाने का भी मुद्दा उठाया। जिसपर अपर नगर आयुक्त ने एक बार फिर सभी विभागाध्क्षो को १५ दिवस के अन्दर अनुपालन आख्या दिये जाने के निर्देश जारी किया है। इसके अलावा शशि कुमार मिश्र ने बताया कि संघ की १७ सूत्रीय मांग पत्र पर समयबद्ध कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश जारी किये गये हैं। कर्मचारियों की पदोन्नित, अस्थायीध्तदर्थ कर्मचारियो का विनियमितीकरण, वर्षो से लम्बित डीए, बोनस, एनएससी, नगर निगम व जलकल कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची, जलकल

कर्मचारियों को पेंशन बुक, सेवानिर्वत पर सम्पूर्ण भुगतान,कर्मचारियों के निलम्बन की कार्रवाई का समयबद्ध निस्तारण, कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतो में कर्मचारियों का पक्ष लेना जरूरी किया जाये, नगर निगम एवं जलकल के समस्त कार्यदायी कर्मचारियों को एक समान न्यूनतम वेतन भत्ता दिये जाने व वर्ष २००५ से २०२१ तक नियमित कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी भविष्य निधि धनराशि का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने समेत १७ सूत्रीय मांगें शामिल रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र, आरपी सिंह, आनन्द मिश्रा अध्यक्ष (लखनऊ), महामंत्री कैसर रजा, सतीश कुमार सिंह, हरिशंकर पांडये, चन्द्रमोहन, उपाध्यक्ष विभा यादव, कुंवर जय सिंह, संतोश श्रीवास्तव, संजय चन्द्रा, कुलदीप चौधरी, अम्बरीश अवस्थी, आयुष पंत आदि प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

स्थानांतरित अराजपत्रित अधिकारियों समेत कर्मियों को तुरंत करें रिलीवः डीजीपी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने शासन स्तर पर स्थानांतरित किये गए अराजपत्रित अधिकारियों और कर्मचारियों को रिलीव न किये जाने पर नाराजगी जताते हुये सभी कमिश्नरेट सहित जोनल अपर पुलिस महानिदेशक को पत्र भेज कर जल्द कार्यमुक्त करने को कहा है। पुलिस महानिदेशक स्थापना नचिकेता झा की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि उप्र पुलिस बल के जिन अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के समयावधि/प्रशासनिक/जनहित एवं अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण आदेश पुलिस महानिदेशक स्तर से निर्गत किए गये है। उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानान्तरित कर्मियों को समय से कार्यमुक्त न किए जाने के कारण कार्मिकों द्वारा न्यायालय में रिट

याचिकाएं योजित की जाती है। जिस समय न्यायालय द्वारा समय से स्थानान्तरण आदेश पर कार्यमुक्त न किए जाने पर विभाग की कार्यप्रणाली पर एकरूपत्ता के आभाव में प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए स्थानान्तरण आदेश का कियान्वयन तत्काल शत् प्रतिशत कराया जाना आवश्यक है, ताकि स्थानान्तरित पुलिस बल के कर्मी समय से स्थानान्तरित जोन/ कमिश्नरेट/जनपद में अपना आगमन समय से कराकर कर्तव्यरत हो जाए। जिससे संबंधित जोन/ कमिश्नरेट /जनपद में जनशक्ति की समस्या उत्पन्न न हो और कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न हो सके। पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि स्थानान्तरण आदेशों में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि स्थानान्तरित कर्मी को १० दिवस के अन्दर कार्यमुक्त कर दिया जाए। साथ ही इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

जानकीपुरम विस्तार में डायरिया का प्रकोप अभी थमा नहीं

लखनऊ। जानकीपुरम विस्तार में डायरिया का प्रकोप अभी थमा नहीं है। अब डायरिया पीड़ित एक किशोरी की भी सांसें थम गईं। डायरिया के तीन नए मरीज भी मिले हैं। इनमें से दो मरीजों को भर्ती कराया गया। इससे पहले एक पुरुष की मौत हो चुकी है। अभी भी इलाके में कई और लोग डायरिया की चपेट में हैं। लगातार मौतों पर भी स्वास्थ्य महकमा हाथ पर हाथ धरे बैठा है। मुहैया कराई जा रही इलाज की सुविधाएं कठघरे में आ रही हैं। फजीहत के बाद सीएमओ ने बुधवार को जानकीपुरम ट्रॉमा सेंटर का जायजा लिया। जानकीपुरम विस्तार के सेक्टर–३, ७ एवं ८ में करीब १० दिनों से डायरिया का प्रकोप है। अब तक १५० से अधिक लोग इसके चपेट में आ चुके हैं। स्थानीय निवासी १२ वर्षीय सरिता बीते गुरुवार से बीमार थी। मूल रूप से बलिया निवासी उमाशंकर सिंह सेक्टर–८ में परिवार के साथ झोपड़ी डालकर रहते हैं। तबीयत खराब होने पर परिवारीजन पहले स्थानीय डॉक्टर की सलाह ली। हालत गंभीर होने पर परिवारीजनों ने किशोरी को जानकीपुरम ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। इलाज के बावजूद मरीज की तबीयत में सुधार नहीं हुआ। नाजुक हाल में डायरिया पीड़ित को बलरामपुर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इमरजेंसी में डक्टरों ने मरीज को देखा। इलाज शुरू किया। मां सरोजनी का आरोप है कि जानकीपुरम ट्रॉमा के डॉक्टरों ने समय रहते मरीज को रेफर नहीं किया। कई बार डक्टरों से मरीज को रेफर करने की गुजारिश की, लेकिन डॉक्टरों ने एक न सुनी। हालत बिगड़ने पर सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां भर्ती करने से मना कर दिया गया। इसके बाद परिजन बलरामपुर अस्पताल पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद सरिता को भर्ती किया गया। सांस लेने में दिक्कत होने उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। देर रात करीब डेढ़ बजे सरिता की सांसें थम गईं। भाई अर्जुन सिंह (१५) को भी डायरिया की शिकायत के बाद ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। इससे पहले शनिवार को बर्तन बेचने वाले राजेश कौशल (५०) की मौत हो चुकी है। अब तक डायरिया से दो मौतें हो चुकी हैं। डायरिया से इलाके में दहाशत है। कई लोगों ने सप्लाई का पानी सीधे पीने से इनकार कर दिया हे। लोग उबालने के बाद पानी को ठंडाकर प्यास बुझाने को मजबूर हैं। जानकीपुरम इलाके में अभी भी नए मरीज मिल रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसका खामियाजा आमजनों को भुगतना पड़ रहा है। जानकीपुरम विस्तार में डायरिया कैसे फैला इसके रहस्य से स्वास्थ्य विभाग पर्दा नहीं उठा पा रहा है। शुरुआत में दूषित पानी पीने से बीमार पड़ने की आशंका जताई गई थी। लेकिन जांच में पानी शुद्ध होने का दावा किया गया। स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र में सिर्फ शिविर लगाकर खानापूरी कर रहा है। बीमार होने पर मरीजों के साथ रेफर करने का खेल खेला जा रहा है। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि किशोरी के डेथ ऑडिट में हाइपोवोलेमिक शॉक विथ सेप्टिसीमिया आया है। क्षेत्र में स्वास्थ्य टीम सक्रिय है। बुधवार को टीम ने ५६ घरों का निरीक्षण किया। शिविर में १५ मरीजों को देखा गया है, जिसमें डायरिया के तीन नए रोगी मिले। जिसमें से दो रोगियों को भर्ती कराया गया है। क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर एण्टी लार्वा रसायन का छिडकाव कराया जा रहा है। बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह का कहना है कि क्षेत्र के अन्तर्गत मामा कालोनी एवं शिव शक्तिनगर में टीमों ने बुधवार को क्षेत्र में १४० घरों का सर्वे करते हुए ६२ मरीजों को देखा। डायरिया का कोई रोगी नही पाया गया। क्षेत्र में एमएमयू के माध्यम से मरीजों को उपचार प्रदान किया गया। जिला मलेरिया अधिकारी की टीम द्वारा क्षेत्र में एण्टी लार्वा रसायन का छिड़काव भी किया गया।

बिहार चुनाव में हो गई डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री, मुजफ्फरपुर की रैली में राहुल ने ऐसे कर दिया जिक्र

नई दिल्ली। कांग्रेस के राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर पाकिस्तान में आतंकी शिविरों के खिलाफ भारत की कार्रवाई तुरंत रोक दी थी। राहुल गांधी का यह बयान, चुनावी राज्य बिहार के मुजफ्फरपुर में श्मतदाता अधिकार यात्राश के तहत आयोजित रैली में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मई में सैन्य संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धविराम में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के अपने दावे को एक बार फिर दोहराए जाने के कुछ घंटों बाद आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे दावा किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों के बीच हस्तक्षेप किया और व्यापार तथा टैरिफ की धमकियों का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री मोदी को इस्लामाबाद के साथ युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने रैली में कहा कि ट्रंप ने आज कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तो मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी को बताया कि वो जो कुछ भी कर रहे

हैं, उसे २४ घंटे के अंदर बंद कर दें। और नरेंद्र मोदी ने २४ घंटे नहीं, बल्कि पाँच घंटे में सब कुछ बंद कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को ष्परमाणु युद्धष में बदलने से रोक दिया है, क्योंकि उन्होंने टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और युद्ध विराम पर सहमत न होने पर किसी भी व्यापार समझौते से इनकार कर दिया था। ट्रंप की ताजा टिप्पणी मंगलवार को व्हाइट हाउस में कैबिनेट की बैठक के दौरान आई, जहाँ उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने मोदी से बात की है। उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत ही शानदार इंसान से बात कर रहा हूँ, भारत के मोदी से। मैंने पूछा, श्तुम्हारे और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है?श फिर मैंने पाकिस्तान से व्यापार के बारे में बात की। मैंने कहा, श्तुम्हारे और भारत के बीच क्या चल रहा है?श यह बहुत लंबे समय से चल रहा है, कभी–कभी सैकड़ों सालों से अलग–अलग नामों से।ष गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान १९४७ में स्वतंत्र राष्ट्र बने, जब उपमहाद्वीप में लगभग २०० वर्षों का ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन समाप्त हुआ। तब तक, वे एक ही देश थे।

दहेज को लेकर पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार

बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पुलिस ने एक महिला की कथित तौर पर दहेज को लेकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार जिले के पकड़ी थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में १७ अगस्त को रिंचू सिंह नामक नवविवाहिता की दहेज को लेकर कथित तौर पर हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने मंगलवार को बताया कि जिले के दोकटी थाना क्षेत्र के वाजीतपुर गांव के राम नरेश सिंह की तहरीर पर विवाहिता के पति अभिजीत सिंह, ससुर अवधेश सिंह, जेठ अभिषेक सिंह और जेठानी रोशनी देवी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। रिंचू की शादी इसी साल अप्रैल में अभिजीत सिंह के साथ हुई थी। ससुराल पक्ष ने शादी के दिन से ही दहेज के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था और १७ अगस्त को दहेज

को लेकर रिंचू की हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने आरोपी पति अभिजीत सिंह को सोमवार को उससा गांव के पास से गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए जेल भेज दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है।

एएमयू की प्रोफेसर विभा शर्मा को पांच सितंबर को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कला संकाय के अंग्रेजी विभाग की संकाय सदस्य प्रोफेसर विभा शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। एएमयू ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि कला संकाय के अंग्रेजी विभाग की संकाय सदस्य प्रो. विभा शर्मा को केंद्रीय उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार (एनएटी) २०२५ के लिए चुना है। प्रोफेसर शर्मा पांच सितंबर (शिक्षक दिवस) को नयीदिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह पुरस्कार ग्रहण करेंगी। प्रो. शर्मा देश भर के २१ पुरस्कार विजेताओं में से एक हैं। इसमें योग्यता प्रमाण पत्र, एक रजत पदक और ५०,००० रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

दिल्ली में यमुना का स्तर खतरे के निशान के करीब, बाढ़ की चेतावनी जारी

नर्द दिल्ली। दिल्ली में यमुना का जलस्तर मंगलवार को चेतावनी के स्तर को पार कर गया। इसके बाद केंद्रीय जल आयोग द्वारा शाम को बाढ़ की चेतावनी जारी की गयी।

यमुना का जलस्तर मंगलवार रात नौ बजे पुराने रेलवे पुल (ओआरबी) पर २०४.५६ मीटर के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले, सुबह नौ बजे यमुना का जलस्तर २०४.५८ मीटर रहा। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ की चेतावनी जारी करते हुए कहा, '' चूंकि पुराने रेलवे पुलका जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है और इसके २०५.३६ मीटर तक पहुंचने की संभावना है, इसलिए सभी अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने–अपने क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखें और संवेदनशील बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई करें। नदी के तटबंधों के भीतर रहने वाले लोगों को चेतावनी दी जाएगी और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था की जाएगी।'' केंद्रीय बाढ़ कक्ष के एक अधिकारी ने कहा, '' जलस्तर में वृद्धि का मुख्य कारण वजीराबाद और हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाना है। पूर्वानुमान है कि जलस्तर में और वृद्धि होगी, लेकिन आज शाम तक इसके खतरे के निशान से नीचे रहने की संभावना है। '' नदी के प्रवाह और संभावित बाढ़ के खतरों पर नजर रखने के लिए पुराना रेलवे पुल एक प्रमुख अवलोकन बिंदु के रूप में कार्य करता है। दिल्ली के लिए चेतावनी चिह्न २०४.५० मीटर, खतरे का निशान २०५.३३ मीटर और निकासी २०६ मीटर पर शुरू होती है। बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली तक पहुंचने में आमतौर पर ४८ से ५० घंटे का समय लेता है। ऊपरी इलाकों से कम मात्रा में पानी छोड़े जाने से भी जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली में यह चेतावनी के निशान के करीब पहुंच गया है।

नाले में गिरे युवक–युवती का शव २६ घंटे बाद बरामद

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में प्रशासन ने कोतवाली थाना क्षेत्र के मछलीशहर पड़ाव पर सोमवार शाम नाले में गिरे युवक–युवती के शवों को २६ घंटे की तलाश के बाद बरामद कर लिया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जिला प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका और अग्निशमन दल की टीमों ने दिन–रात मेहनत की और आखिरकार मंगलवार शाम राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की विशेष टीम ने शव बरामद कर लिए। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार शाम मैनहोल में गिरने के बाद नाले में बहे युवक–युवती के शव २६ घंटे बाद पठानटोलिया में मिले। श्रीवास्तव ने बताया, मृतक युवती की पहचान जौनपुर निवासी प्राची मिश्रा (२६) के रूप में हुई है। प्राची मिश्रा ब्यूटी पार्लर से पैदल घर के लिए निकली थी। मछलीशहर बस अड्डे पर भारी बारिश के कारण हुए जलभराव के कारण वह नाले में गिर गई और लापता हो गई। उन्होंने बताया कि इसी दौरान प्राची को बचाने के प्रयास में प्रयागराज के फूलपुर निवासी समीर (१८) भी नाले में बह गया। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका और दमकल विभाग की टीमें कल शाम से ही इन दोनों की तलाश कर रही थीं। उन्होंने बताया कि आज सुबह से ही एसडीआरएफ और पीएसी को भी तैनात कर दिया गया था। पूरे दिन चले बचाव अभियान के बाद मंगलवार देर शाम दोनों मृतकों के शव घटनास्थल से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर बरामद हुए। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नगर मजिस्ट्रेट इंद्रनंदन सिंह ने बताया कि यह घटना सोमवार शाम करीब छह बजे की है। सोमवार को इन दोनों को बचाने की कोशिश में एक तीसरे व्यक्ति ई–रिक्शा चालक शिव गौतम (२५) की भी पानी के बहाव में फंसकर मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कल उसका शव बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया था।

देखभाल के अभाव में दो सगे भाइयों की मौत, विसरा सुरक्षित

लखनऊ। लखनऊ के सहादतगंज थाना क्षेत्र स्थित एक घर में देखभाल के अभाव में दो सगे भाइयों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं है। जिसको देखते हुए मृतकों के विसरा को सुरक्षित रखवा दिया गया है। पुलिस ने बताया कि सहादतगंज थाना निवासी राजू (६२) और रवि पाहवा (५८) अमीनाबाद निवासी अपनी बहन को छोड़कर परिवार में अकेले थे। उनके माता–पिता और पत्नी का कोई अता–पता नहीं है। दोनों भाई पिछले एक हफ्ते से बीमार थे, लेकिन उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। पड़ोसियों ने बताया कि दोनों भाई बेहद साधारण जीवन जीते थे और कूड़ा बीनकर अपनी आजीविका चलाते थे। पड़ोसियों ने बताया कि उनके घर से तेज बदबू आने की शिकायत के बाद पुलिस को को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर का दरवाजा खोला और दोनों भाइयों के शव बरामद किए। प्रारंभिक जांच में शव कई दिन पुराने प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस ने मृतकों की बहन को अमीनाबाद में सूचित किया, जो परिवार का एकमात्र जीवित रिश्तेदार है। सहादतगंज थाना प्रभारी अजय नारायण सिंह ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टम र्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नही हो सकी है। जिसके चलते बिसरा सुरक्षित रखाव दिया गया है। साथ ही पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

ऑपरेशन सिंदूर ने स्वदेशी मंचों और हथियारों की सफलता को किया प्रदर्शित, महू में बोले राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि अ परेशन सिंदूर ने भारत को आज के युग में सूचना और साइबर युद्ध का महत्व सिखाया है। उन्होंने अपने बुनियादी ढांचे को और भी मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मध्य प्रदेश के महू में प्रथम त्रि–सेवा संगोष्ठी श्रण संवादश को संबोधित करते हुए, रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भरता को ष्परम आवश्यकष बताया और कहा कि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, हालाँकि भारत ने इस रास्ते पर काफी प्रगति की है। राजनाथ ने इस कार्यक्रम में कहा कि अ परेशन सिंदूर ने हमें आज के युग में सूचना और साइबर युद्ध के महत्व को सिखाया है। यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमारी सूचना और साइबर संरचना को और भी मजबूत बनाया जाए। मेरा मानना घ्छै कि हमें इस मामले पर गहराई से विचार और गहन विचार करना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अ परेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी रक्षा उपकरणों की सराहना की और कहा कि इसकी सफलता ने भारत को रक्षा

क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का रोडमैप दिया है। उन्होंने कहा कि अ परेशन सिंदूर हमारे स्वदेशी प्लेटफार्मों, उपकरणों और हथियार प्रणालियों की सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है। इसकी उपलब्धियों ने एक बार फिर रेखांकित किया है कि आने वाले समय में आत्मनिर्भरता एक परम आवश्यकता है। हमने आत्मनिर्भरता के पथ पर निश्चित रूप से उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन अभी भी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। मंत्री ने युद्ध के मैदान में बदलते नियमों का जिक्र करते हुए कहा कि जो देश युद्ध में नेतृत्व करता है, वही खेल को नियंत्रित करता हैष। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में, जो भी देश युद्ध का मैदान तय करता है, वही खेल और उसके नियमों को नियंत्रित करता है। दूसरों के पास इसका जवाब देने और उन शर्तों के क्षेत्र में कदम रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो उन्होंने खुद नहीं चुनी हैं। हमारा प्रयास युद्ध के मैदान और खेल के नियमों को स्वयं परिभाषित करना होना चाहिए, जिससे विरोधी पक्ष को वहाँ लड़ने के लिए मजबूर किया जा सके ताकि बढ़त हमेशा हमारे पास बनी रहे। अ परेशन सिंदूर की सफलता अपने आप में एक आदर्श उदाहरण है।

लखनऊ में गृहकर बकाये पर २४ भवन सील, वसूले ११.४४ लाख

लखनऊ। नगर निगम ने गृहकर के बड़े बकायेदारों के खिलाफ बुध ावार को सभी जोनों में अभियान चलाया। बड़े बकायेदारों के खिलाफ कुर्की व सीलिंग की कार्रवाई करते हुए २४ भवन सील कर दिए। आंशिक भुगतान के रूप में ११.४४ लाख रुपये जमा कराए। बकाया गृहकर जमा न करने पर जोन १ के मदन मोहन मालवीय मार्ग स्थित गोल्ड अ फसेट प्रिंटर्स और गोखले मार्ग स्थित एकेजी कन्सल्टेंट्स लिमिटेड नर्सिंग होम को सील कर दिया। नगर आयुक्त ने बताया कि ३१ अगस्त तक एकमुश्त यूजर चार्ज जमा करने पर गृहकर में १० प्रतिशत और

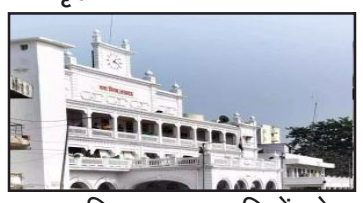

व्यावसायिक भवन स्वामियों को ५ प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि इस अवसर का लाभ उठाकर समय से अपना गृहकर जमा करें।

दिल्ली में गाय के गोबर को लेकर झगड़ा चोरी तक पहुंचा, एक व्यक्ति गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली में गाय के गोबर को लेकर पड़ोसियों के बीच जारी झगड़े ने एक विचित्र मोड़ ले लिया, जिसमें २५ वर्षीय व्यक्ति ने बदला लेने के लिए कथित तौर पर अपने पड़ोसी की दुकान में डाका डाला। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली के सागरपुर इलाके में आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया और उसके पास से चोरी की १५,००० रुपये नकदी बरामद की। पुलिस ने बताया कि दुकानदार ने २१ अगस्त को एक शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसकी दुकान से पैसे चुराए गए हैं। जांच के दौरान पुलिस ने उसके पड़ोसी संदीप की पहचान मुख्य संदिग्ध के रूप में की और उसे २५ अगस्त को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान संदीप ने चोरी का जुर्म कबूल कर लिया और घटना के पीछे के इरादे के बारे में बताया। संदीप ने पुलिस को बताया कि उसके पड़ोसी की गायें आए दिन उसके घर के आसपास घूमती थीं और उसके दरवाजे के सामने ही गोबर कर देती थीं। बार–बार शिकायत करने के बावजूद दुकानदार ने कोई कदम नहीं उठाया और एक बार तो उसने सार्वजनिक रूप से उससे गाली–गलौज की। पुलिस ने बताया कि इससे ''आक्रोशित'' संदीप ने पड़ोसी की दुकान का ताला तोड़कर चोरी कर बदला लेने का फैसला किया।

सुप्रीम कोर्ट को मिलने जा रहे २ नए जज, जस्टिस अराधे और जस्टिस पंचोली के नाम को केंद्र ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। इस संबंध में, केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति आलोक अराधे और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने को मंजूरी दे दी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर कहा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, (प) न्यायमूर्ति श्री आलोक अराधे, मुख्य न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय और (पप) न्यायमूर्ति श्री विपुल मनुभाई पंचोली, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय

को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। ध्यान रहे कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वींत पद ३४ हैं, लेकिन यह केवल ३२ न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा है। अब, न्यायमूर्ति आलोक अराधे और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पदोन्नति से दोनों रिक्तियाँ भर जाएँगी, और सर्वोच्च न्यायालय एक बार फिर पूरी क्षमता से कार्य करेगा। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति नागरत्ना की पाँच सदस्यीय क लेजियम ने २५ अगस्त को बैठक की और केंद्र को ब म्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति पंचोली के नामों की सिफारिश शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की। हालांकि, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने न्यायमूर्ति पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने के प्रस्ताव पर कड़ी असहमति जताई थी, जैसा कि बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट में बताया गया है।

आपराधिक मामले को अनुचित अवधि तक लंबा खींचना एक प्रकार की पीड़ा है : न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी आपराधिक मामले को अनुचित अवधि तक खींचना एक प्रकार की पीड़ा है, जो कार्यवाही का सामना कर रहे व्यक्ति के लिए मानसिक कारावास के समान है। न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया और ए.एस. चंदुरकर ने यह टिप्पणी उस समय की, जब उन्होंने एक महिला को भ्रष्टाचार के मामले में सुनाई गई सजा को घटाकर केवल पहले से जेल में बिताई जा चुकी अवधि तक सीमित कर दिया। उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए पीठ ने कहा कि यह घटना २२ वर्ष पहले घटित हुई थी और महिला अब ७५ वर्ष की हो चुकी है। अदालत ने हालांकि उन पर लगाए गए जुर्माने को मूल जुर्माने से २५,००० रुपये अधिक कर दिया। पीठ ने २१ अगस्त को कहा, "किसी आपराधिक मामले को अनुचित अवधि तक खींचना अपने आप में एक प्रकार की पीड़ा है। ऐसी कार्यवाही का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए यह मानसिक कारावास के समान है।" उच्चतम न्यायालय का यह फैसला महिला द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के अगस्त २०१० के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर आया, जिसमें अधीनस्थ अदालत के आदेश की पुष्टि की गई थी। निचली अदालत ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में कार्यरत महिला को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और उसे एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि सितंबर २००२ में उसने ३०० रुपये की अवैध रिश्वत की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि जो व्यक्ति दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करता है और हर दिन मुकदमे के परिणाम का इंतजार करता है, वह अपना समय परेशानी में बिताता है। पीठ ने कहा, "न्याय प्रशासन की वर्तमान प्रणाली में, जिसमें कार्यवाही अक्सर अनुचित रूप से लंबी और असहनीय हो जाती है, लंबा समय बीतने से व्यक्ति को मानसिक पीड़ा होती है।

जनप्रतिनिधि और प्रशासन के प्रयासों से खातेदारों ने भूमिहीन गरीब परिवार को दिया ८२५ वर्गफुट का प्लॉट

लखीमपुर खीरी। गोला गोकर्णनाथ तहसील क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण से जुड़ा एक मामला प्रशासनिक पहल और मानवीय दृष्टिकोण से मिसाल बन गया। उप जिलाधि ाकारी युगांतर त्रिपाठी ने बताया कि जांच में सामने आया कि मीना देवी पत्नी उधन, जिनके पति उध ान पुत्र बुद्धालाल आर्थिक रूप से बेहद कमजोर और भूमिहीन हैं, विवादित भूमि पर निवास कर रहे थे। स्थिति अवगत कराने पर खातेदारों ने स्वेच्छा से १५ग्५५ = ८२५ वर्गफुट भूमि देने का निर्णय लिया। आज दिनांक २७ अगस्त २०२५ को खातेदार ने ६,२५० रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा कर दानपत्र तैयार कराया और उपनिबंधक कार्यालय गोला गोकर्णनाथ में मीना देवी के नाम विलेख की कार्यवाही पूरी की। दान में मिली भूमि पर टीनशेड लगाकर अब उधन पुत्र बुद्धालाल अपने परिवार संग रह रहे हैं।

उद्योग व्यापार संगठन ने बांटी राहत राशन किटें

सुनील शर्मा लखीमपुर खीरी। उ. प्र. उद्योग व्यापार संगठन (पंजी.) लखीमपुर खीरी द्वारा आज खानीपुर बाढ़ राहत चौकी पर जिला प्रशासन की देखरेख में पीड़ितों को १०० बाढ़ राहत राशन किट का वितरण संगठन द्वारा किया गया। इस अवसर पर संगठन के जिलाध यक्ष विजय शुक्ला जिला महामंत्री गोपाल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता,पवन गुप्ता

जी,संदीप मिश्राजी,रितेश मित्तलजी,श्यामजी गुप्ता,प्रांजल शुक्ला, संजीव मिश्रा जी व अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। जिला प्रशासन की तरफ से भी अधिकारीगण मौजूद रहे।

अमेरिका को जवाब देने की तैयारी! PMO में मोदी की बड़ी बैठक, २७ अगस्त से लगने वाला है ५० प्रतिशत टैरिफ

नई दिल्ली। अमेरिका ने भारत से आने वाले उत्पादों पर ५०: टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसके लिए उसने अधिसूचना भी जारी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर एक अहम बैठक कर रहे हैं। यह बैठक पीएमओ में हो रही है, जिसमें उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। इसके अलावा वाणिज्य और वित्त मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर संशोधित टैरिफ लागू करने की योजना बनाई है, जो २७ अगस्त की रात १२रू०१ बजे के बाद प्रभावी होंगे। एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है, जिसमें भारतीय उत्पादों पर २५ प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है। सूचना में स्पष्ट किया गया है कि ये बढ़े हुए शुल्क उन भारतीय वस्तुओं पर लागू होंगे जो रात १२रू०१ बजे या उसके बाद अमेरिकी बाजार में उपभोग के लिए प्रवेश करेंगी। ये शुल्क उस समय के बाद उपयोग के लिए अमेरिकी गोदामों से निकाले गए सामानों पर भी लागू होंगे। अमेरिका के अनुसार, यह बढ़ोतरी नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद का दंड है, जिसके बारे में ट्रंप ने कहा था कि यह यूक्रेन में मास्को के युद्ध को

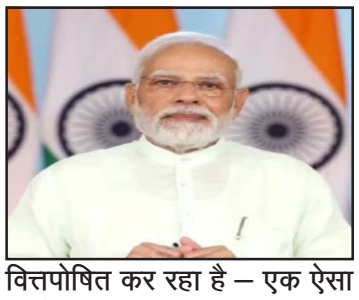

वित्तपोषित कर रहा है — एक ऐसा आरोप जिसका दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने कड़ा खंडन किया है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता में अटूट विश्वास व्यक्त करते हुए ढ़ता से कहा है कि स्वदेशी (स्वदेशी) आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले वर्षों में, प्रत्येक नागरिक स्वदेशी उत्पादों और प्रथाओं को अपनाते हुए 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र का समर्थन करेगा। २०४७ तक, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के १०० वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएगा, तब निस्संदेह यह एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत ने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत के निर्माण का आधार बनाया है। किसानों, पशुपालकों, छोटे उद्यमियों और मछुआरों की ताकत से देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को दो दशकों के प्रयासों से निर्मित गुजरात से अपार शक्ति मिलती है। राज्य के डेयरी, सहकारिता और पशुपालन क्षेत्र — जहाँ महिलाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं— विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। उन्होंने किसानों, व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को आश्वासन दिया कि उनके हित उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। कभी संसाधनों की कमी के कारण उपेक्षित, गुजरात आज भारत के विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है।

डीएम ने की राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा, अफसरों को दिए निर्देश

लखीमपुर खीरी। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में जनपद के सभी राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राजस्व मामलों का निस्तारण पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और तय समय सीमा के भीतर होना चाहिए। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। समीक्षा के दौरान उन्होंने धारा २४ (उत्तराधिकार), धारा ३४ (नामांतरण), धारा ६७ व धारा ११६ (सीमांकन) से संबंधित वादों पर विशेष जोर देते हुए कहा कि हर मामले का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लंबित मामलों में अनावश्यक देरी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने सभी एसडीएम, एसडीएम न्यायिक, तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि तिथि निर्धारण व सुनवाई की प्रक्रिया नियमित रूप से संचालित की जाए। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने अंत में यह भी कहा कि राजस्व न्यायालयों की

कार्यप्रणाली जनता के विश्वास से जुड़ी है, और इसमें पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि वादों की सुनवाई पूरी गंभीरता व संवेदनशीलता के साथ की जाए ताकि न्यायिक प्रक्रिया में लोगों का भरोसा और मजबूत हो सके। इस समीक्षा बैठक में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, सभी उपजिलाधिकारी (न्यायिक) शामिल रहे। बैठक का संचालन एडीएम (न्यायिक) अनिल कुमार रस्तोगी ने किया।

खीरी की ६४ बेटियां बनीं मुख्य सेविका

लखीमपुर खीरी, २७ अगस्त। जिले के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन, लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (**UPSSSC**) द्वारा निष्पक्ष एवं

पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित खीरी जिले की ६४ नवचयनित मुख्य सेविकाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर खीरी की बालिकाओं के चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी साफ झलक रही थी। विशेष बात यह रही कि सुदूरवर्ती वनक्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली थारू जनजाति की ११ बालिकाओं का भी चयन मुख्य सेविका पद पर हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को जनजातीय समाज की बेटियों की मेहनत और बदलते परिवेश का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में खीरी जिले की नवचयनित मुख्य सेविका गुरप्रीत कौर और थारू जनजाति क्षेत्र की पूजा सिंह ने मुख्यमंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर अपने सपनों को नई उड़ान दी। वहीं सुरमा गांव की नंदोराना से मुख्यमंत्री ने संवाद किया। बताते चलें कि डीपीओ भारत प्रसाद की देखरेख में यह सभी ६४ नव चयनित मुख्य सेविका लोकभवन पहुंची थी। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बुधवार को जिले की सुरमा गांव की नंदोराना की खुशी देखने लायक थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आमने–सामने संवाद का मौका मिला तो उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास झलक उठा। नंदोराना ने बताया कि कठिन हालातों में पढ़ाई जारी रखी। प्रदेश सरकार की पारदर्शी व सूचितापूर्ण भर्ती प्रक्रिया ने उन्हें नया जीवन दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी व पूरी प्रदेश सरकार के प्रति आभार जताया। गौरतलब है कि नंदोराना अब तक शिक्षामित्र के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थीं। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वह अब मुख्य सेविका के रूप में कार्यभार संभालेंगी। सुरमा गांव की नंदोराना बताती हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर बहुत खुशी हुई। पारदर्शी भर्ती ने हमें सम्मान और नई पहचान दी है। बताते चलें कि लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (**UPSSSC**) द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित २,४२५ मुख्य सेविकाओं एवं १३ फार्मासिस्टों को नियुक्ति–पत्र वितरित किए गए। जनपद की ६४ नवचयनित मुख्य सेविकाओं को लोक भवन में मा. मुख्यमंत्री जी से नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि न केवल चयनित मुख्य सेविकाओं की मेहनत और लगन का परिणाम है, बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का क्षण भी है। अब आप सब पर बच्चों के पोषण, शिक्षा और समाज में जागरूकता

लाने की बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से निभाकर आप आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार सकती हैं।

प्रेमानंद महाराज पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य की टिप्पणी से दो खेमों में बँटा संत समाज, शंकराचार्य भी विवाद में कूदे

मथुरा। धार्मिक जगत में इन दिनों संत प्रेमानंद महाराज को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको बता दें कि जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में यह कहकर हलचल मचा दी थे कि वह प्रेमानंद महाराज को 'चमत्कारी' नहीं मानते। उन्होंने यहाँ तक चुनौती दे डाली कि यदि वह वास्तव में चमत्कारी हैं तो अपने संस्कृत श्लोकों का हिंदी में अर्थ बताकर दिखाएँ। इस बयान ने संत समाज को दो खेमों में बाँट दिया है।

वृंदावन और ब्रज के कई संतों ने रामभद्राचार्य जी की टिप्पणी को अहंकार से प्रेरित बताया है। साधक मधुसूदन दास ने कहा कि "भक्ति का भाषा से कोई लेना–देना नहीं होता। कोई चाइनीज, कोई फ्रेंच या कोई अन्य भाषा बोलने वाला भी जब भक्ति करता है तो भगवान स्वीकार करते हैं। संस्कृत न आने से भक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।" वहीं अभिदास महाराज का मानना है कि प्रेमानंद महाराज कलियुग के दिव्य संत हैं, जिन्होंने लाखों युवाओं को गलत रास्तों से हटाकर सत्कर्म की ओर अग्रसर किया। ऐसे संत पर टिप्पणी करना उचित नहीं। वहीं दिनेश फलाहारी ने तो यहां तक कह दिया कि "इतना अहंकार तो रावण में भी नहीं था। प्रेमानंद महाराज का जीवन सादगी भरा है और उनके पास कोई संपत्ति नहीं, जबकि रामभद्राचार्य के पास संपत्ति है। प्रेमानंद के पास केवल राधा नाम की शक्ति है।" वहीं अनमोल शास्त्री ने प्रेमानंद महाराज को "युवाओं के दिल की धड़कन" बताते हुए कहा कि किसी संत के लिए यह शोभनीय नहीं कि वह दूसरे को छोटा बताए। ऐसी ही प्रतिक्रियाएं कई अन्य साधकों की भी रहीं। दूसरी ओर रामभद्राचार्य जी के बयान के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रेमानंद महाराज की भक्ति पद्धति पर प्रश्न उठाए हैं। उनका कहना है कि शास्त्र और ज्ञान के बिना अध्यात्म अधूरा है। इसी विचारधारा को लेकर उनका झुकाव रामभद्राचार्य के पक्ष में माना जा रहा है। इस विवाद ने साफ कर दिया है कि संत समाज एकमत नहीं है। एक पक्ष प्रेमानंद महाराज को "कलियुग का दिव्य संत" मानते हुए उन्हें जनमानस का मार्गदर्शक बताता है, जबकि दूसरा पक्ष उनके चमत्कार और आध्यात्मिक ज्ञान पर प्रश्न खड़े करता है। देखा जाये तो भक्ति, ज्ञान और परंपरा को लेकर उपजा यह विवाद इस समय मथुरा–वृंदावन से लेकर काशी तक चर्चा का विषय बना हुआ है। जहाँ एक ओर प्रेमानंद महाराज युवाओं के बीच लोकप्रियता और साधना की सरल धारा के प्रतीक माने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर विद्वत परंपरा से जुड़े संत इस शैली को अधूरा मानते हैं। यानी संत समाज आज एक बार फिर उसी शाश्वत प्रश्न के सामने खड़ा हैं क्या भक्ति केवल ज्ञान और भाषा से सिद्ध होती है, या वह भाव और श्रद्धा में ही पूर्ण है?

यूपी के अंदर कार्य करने वाले युवाओं को न्यूनतम वेतन की मिलेगी गारंटीः सीएम योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कार्य करने वाले प्रत्येक युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। कोई भी कंपनी या नियुक्ता कर्मचारी का शोषण नहीं कर पाएगा। नियुक्ति देने वाली कंपनियां अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेंगी, जबकि इसके अतिरिक्त चार्जेज की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यह व्यवस्था युवाओं को सम्मानजनक रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित तीन दिवसीय "रोजगार महाकुंभ २०२५" का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है, जहां काम करने वाले हर युवा को न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम वेतन की गारंटी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को अपार ऊर्जा का स्रोत बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी युवा आबादी इस राज्य के लिए सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि आज यूपी की प्रतिभा की मांग देश–दुनिया में हो रही है, और जो प्रदेश कभी रोजगार के लिए पलायन का दंश झेलता था, आज वही रोजगार उपलब्ध करा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी पूरा–का–पूरा गांव रोजगार के लिए प्रदेश छोड़कर पलायन करता था, लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश अपने भीतर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। यह परिवर्तन बीते ८ वर्षों में हुए सुनियोजित प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज यूपी की प्रतिभा की मांग केवल देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में हो रही है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

के मिशन रोजगार और विकसित भारत के संकल्प का हिस्सा है। हर युवा को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलना जरूरी है। जहां अवसर मिला, वहां इन युवाओं ने अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य से लोहा मनवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में "एक जिला एक उत्पाद" (ODOP) योजना के जरिए परंपरागत उद्यमों को नई पहचान दी गई है। एमएसएमई सेक्टर में ६६ लाख यूनिट पुनर्जीवित हुए हैं। कोरोना काल में जब ४० लाख से अधिक प्रवासी कामगार लौटे, तब इन्हीं एमएसएमई यूनिट्स ने ६० प्रतिशत को रोजगार दिया, और वे आज भी उसी व्यवस्था से जुड़े हैं। सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने एमएसएमई यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उद्यमियों को ५ लाख रुपये का सुरक्षा बीमा कवर उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक यूनिट २ से १० युवाओं को रोजगार दे रही है, तो लाखों–करोड़ों लोग प्रदेश में सम्मानजनक काम पा रहे हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार कर रहा है। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनथ ने कहा कि परंपरागत कारीगरों और हस्तशिल्पियों को सम्मान देने के लिए "विश्वकर्मा श्रम सम्मान" और "पीएम विश्वकर्मा" योजनाएं लागू की गई हैं। बढ़ई, राजमिस्त्री, लोहार, सोनार, कुम्हार, मोची, नाई जैसे परंपरागत कामगारों को मुफ्त टूलकिट, सस्ता ऋण और ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके जरिए लाखों लोगों को रोजगार और सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि २४ जनवरी २०२५ को शुरू हुई "सीएम युवा उद्यमी स्कीम" के तहत २१ से ४० वर्ष तक के युवाओं को बिना गारंटी ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें किसी भी युवा की उसकी जाति उसका मत उसका मजहब उसका चेहरा देखकर के नहीं बल्कि उसकी रुचि के अनुसार उसे यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अब तक ७०,००० से अधिक युवाओं ने इस स्कीम से जुड़कर अपने उद्यम स्थापित किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि बीते ८ वर्षों में पारदर्शिता के साथ ८.५ लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसमें पुलिस विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पीडब्ल्यूडी और विश्वविद्यालयों में भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हैं। इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाला देश के अंदर सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती आती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के चलते प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बना है। पिछले ८ वर्षों में ३३ से अधिक सेक्टोरियल प लिसी लागू की गईं। इन्वेस्ट यूपी पोर्टल, निवेश मित्र और सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के जरिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई। परिणामस्वरूप १५ लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश जमीनी स्तर पर उतरे हैं और ६० लाख युवाओं को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन और स्किल डेवलपमेंट मिशन के जरिए युवाओं को नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोल जी, रोबोटिक्स और इंटरनेट अ फ थिंग्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। टाटा टेक्नोल जी के सहयोग से आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में नई लैब और कोर्स शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विदेश जाने वाले युवाओं को भाषा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जर्मनी जाने वालों को जर्मन भाषा, जापान जाने वालों को जापानी और अन्य देशों में जाने वालों को उनकी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वहां पहुंचने के बाद युवाओं को प्रशिक्षण या भाषा की वजह से कठिनाई न झेलनी पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि हर टेक्नोलॉजी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वह समय के अनुरूप बदलती है हमें समाज के मांग के अनुरूप अपने आप को अपडेट करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के हितों की रक्षा और उद्योगों की सुचारुता दोनों को ध्यान में रखते हुए श्रम कानूनों में सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से श्रमिक का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। श्रमिक का पूरा वेतन मिलना अनिवार्य होगा, जबकि अतिरिक्त चार्जेज सरकार अपने स्तर पर वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रोजगार महाकुंभ युवाओं और इंडस्ट्री को जोड़ने का मंच है। इससे न केवल नौकरियां मिलेंगी बल्कि नई टेक्नोल जी की मांग के अनुरूप ट्रेनिंग और कोर्स भी तय होंगे। उन्होंने कहा कि जब श्रमिक और अन्नदाता खुशहाल होंगे, तब ही देश और प्रदेश खुशहाल होगा। यह सुनिश्चित होते ही विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी।

कारागार मंत्री श्री दारा सिंह चौहान ने कारागार प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित दीक्षांत परेड का मान प्रणाम ग्रहण किया

लखनऊ। डॉ० सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में आयोजित दीक्षांत परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कारागार मंत्री श्री दारा सिंह चौहान ने प्रशिक्षु अधिकारियों और जेल वार्डरों को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रशिक्षण की समाप्ति नहीं बल्कि यह एक नई यात्रा, नई जिम्मेदारी और नए संकल्प की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि कारागार सेवा को केवल नौकरी नहीं बल्कि एक पवित्र दायित्व समझते हुए प्रशिक्षुओं को ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और मानवता के साथ कार्य करना होगा। मंत्री श्री चौहान ने कहा कि १९४० में स्थापित डॉ ० सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान एशिया का पहला जेल प्रशिक्षण संस्थान है, जिसने अब तक १,७१९ अधिकारियों और १३,२७७ जेल वार्डरों को प्रशिक्षित कर सेवा में योगदान देने का गौरवशाली इतिहास बनाया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस संस्थान से भारत के साथ–साथ नेपाल, तंजानिया और सूडान जैसे देशों के कारागार कर्मी भी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जो इसकी अंतरराष्ट्रीय पहचान का प्रमाण है। दीक्षांत परेड में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के कुल १३१ प्रशिक्षु शामिल हुए। इनमें उत्तर प्रदेश राज्य के ०८ डिप्टी जेलर, छत्तीसगढ़ राज्य के ०३ जेल अधीक्षक तथा ०६ सहायक जेल अधीक्षक (१२०वाँ सत्र)

और ११४ प्रशिक्षु जेल वार्डर (१७७वाँ सत्र) सम्मिलित रहे। कार्यक्रम में निरीक्षण करते हुए कारागार मंत्री जी ने प्रशिक्षुओं के अनुशासन और प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की अश्विनी पूजा तिर्की (बेस्ट कैडेट अधिकारी संवर्ग) और उत्तराखंड की दिव्या चौहान (बेस्ट कैडेट जेल वार्डर संवर्ग) को महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रेरणादायी उदाहरण बताते हुए सराहना की। इस अवसर पर महानिदेशक कारागार श्री पी. सी. मीना ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान आचरण नियम, नए आपराधिक कानून, जेंडर संवेदीकरण, ई–प्रिजन, मनोविज्ञान, अपराधशास्त्र, समाजशास्त्र और जेल मैनुअल जैसे विषयों पर गहन अध्ययन कराया गया, साथ ही शारीरिक दक्षता और अनुशासन को भी प्राथमिकता दी गई। समारोह के अंत में मंत्री जी ने सभी प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि वे कारागार विभाग की कार्यप्रणाली में नए मानक स्थापित करें और अपने कार्य से समाज को यह संदेश दें कि कारागार सेवा, न्याय, सुधार और मानवता का आधार है।

मुख्यमंत्री वैष्णो देवी यात्रा में प्राकृतिक आपदा में मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा में हुए प्राकृतिक आपदा की चपेट में आये मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जी ने कालकवलित हुए उत्तरप्रदेश के निवासी समस्त मृतक परिजनों को ४ लाख की आर्थिक सहायता के दिये निर्देश। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को मृतकों के शव उनके घर पहुंचाए जाने की व्यवस्था करने के भी दिये निर्देश।

विधायक ने खोली नगर निगम की पोल

लखनऊ। सीएम योगी ने पिछले दिनों रुनगर विकास विभाग की समीक्षा में भले ही क्लीन चिट दे दी है लेकिन लखनऊ के एक भाजपा विधायक रुराजेश्वर सिंह ने नगर विकास विभाग और लखनऊ नगर निगम की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं

।इस सम्बन्ध में सीएम योगी को पत्र भी लिखा है। लखनऊ में सरोजनी नगर से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह , नगर विकास मंत्री ए के शर्मा, के विभाग, नगर विकास और लखनऊ नगर निगम पर सीध ो आरोप लगाये है। भाजपा विधायक ने अपने पत्र में साफ लिखा है कि हर वर्ष लखनऊ नगर निगम करोड़ों रुपए का बजट सुधार के नाम पर खर्च करता है। सड़क निर्माण, नाली निर्माण, नाला सफाई । उसके बाद भी थोड़ी ही बरसात से लखनऊ में कई इलाकों में जलभराव हो जाता है जिससे आम जनता परेशान होती है उन्होंने ने नगर विकास विभाग, और लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मुख्यमंत्री से मांग की। इसके साथ ही एक कमेटी बना कर उनके कार्य की समीक्षा कराने की भी मांग की है ? यह वहीं लखनऊ नगर निगम है जिसको देश में स्वच्छता अभियान के तीसरा स्थान मिला है। इसके बाद भी भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह द्वारा अपनी ही सरकार के नगर विकास विभाग और लखनऊ नगर निगम पर सवाल खड़ा कर दिया है ?

एक सितंबर से फिर चलेगा 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' अभियान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एक से ३० सितंबर के बीच 'नो हेलमेट, नो फ्यूलश विशेष सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जायेगा। यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति (डीआरएससी) के समन्वय से चलाया जाएगा, ताकि जिला स्तर पर सभी संबंधित विभाग एक साथ नागरिक सुरक्षा के इस उद्देश्यमूलक प्रयास को आगे बढ़ाएं। इस अवधि में पुलिस, राजस्वजिला प्रशासन तथा परिवहन विभाग के अधिकारी प्रवर्तन की मुख्य जिम्मेदारी निभायेंगे। सरकार ने आमजन से अपील की है कि वे इन प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग करें। अधिकृत सूत्रों ने बुधवार को बताया कि यह पहल पूर्णतः विधिसम्मत एवं जनहितैषी है। मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ की धारा १२९ दोपहिया चालक तथा पिलियन के लिए हेलमेट को अनिवार्य करती है, जबकि धारा १९४डी उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है। उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति द्वारा भी राज्यों को हेलमेट अनुपालन को प्राथमिकता देने का परामर्श दिया गया है। योगी सरकार ने कहा कि 'नो हेलमेट, नो फ्यूलश

का उद्देश्य दण्डित करना नहीं, बल्कि नागरिकों को कानून के अनुरूप सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा कि अभियान पूरी तरह से सार्वजनिक हित में है। पूर्व के अनुभव बताते हैं कि दोपहिया वाहन स्वामी शीघ्र ही हेलमेट के साथ आने की आदत विकसित कर लेते हैं। इससे ईंधन बिक्री पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। तेल विपणन कंपनियों तथा सभी पेट्रोल पम्प संचालकों से अनुरोध है कि वे इस प्रयास में सक्रिय सहयोग दें। खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से पेट्रोल पम्प स्तर पर आवश्यक समन्वय निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। सूचना एवं जनसम्पर्क तंत्र जन–जागरूकता के प्रसार में सहयोग करेगा। नागरिक, उद्योग और प्रशासन मिलकर ही सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु एवं गंभीर चोटों को कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर ठोस कदम बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' दण्ड नहीं, बल्कि सुरक्षा का संकल्प है। यह अभियान एक से ३० सितम्बर तक जिलाधिकारी के नेतृत्व, डीआरएससी के समन्वय और पुलिस–प्रशासन–परिवहन अधिकारियों के प्रवर्तन के साथ चलेगा। सभी नागरिकों, पेट्रोल पम्प संचालकों और तेल कंपनियों से अपील है कि वे इसमें पूर्ण सहयोग दें। 'हेलमेट पहले, ईंधन बाद में' को नियम बनाएं, क्योंकि हेलमेट पहनना जीवन का सबसे सरल बीमा है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन १७ व १८ सितम्बर को लखनऊ कौशल महोत्सव का आयोजन करेगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आगामी १७ व १८ सितम्बर को लखनऊ कौशल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के सुगम

संचालन और प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारी के लिए कौशल विकास मिशन मुख्यालय में अपर मिशन निदेशक प्रिया सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गयी। बैठक में गठित चार सदस्यीय टीम ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की और महोत्सव को सफल बनाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की। इस दौरान प्रतिभागियों की सुविधा, प्रशिक्षण साझेदारों की भागीदारी, उद्योगों के साथ समन्वय तथा युवाओं तक अधिकतम सूचना पहुँचाने के लिए रणनीति पर विचार–विमर्श किया गया। अपर मिशन निदेशक प्रिया सिंह ने कहा कि लखनऊ कौशल महोत्सव युवाओं के लिए एक सशक्त अवसर होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमशीलता से जुड़ी संभावनाओं से परिचय कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएँ समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरी की जाएं। **India Skills Competition** २०२५ की तैयारियों को लेकर भी मिशन मुख्यालय में अपर मिशन निदेशक प्रिया सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मिशन के वित्त नियंत्रक संदीप कुमार, सहायक निदेशक डॉ. एम.के. सिंह, सहायक प्रबंधक राम सहारे, सहायक प्रबंधक शिखा शुक्ला, क्व्ळझ्ल के स्टेट प्रोग्राम मैनेजर श्री राजू पटेल, **ITOT** के प्रतिनिधि, **NSDC** के स्टेट इंगेजमेंट अ फिसर विनय द्विवेदी की उपस्थिति में कार्यक्रम के प्रभावी अनुश्रवण, क्रियान्वयन एवं सुचारू संचालन हेतु रणनीति बनाये जाने पर चर्चा की गई।

हमारे अन्य प्रतिनिधि

lat; ckti sbZ

lhrkiqj

eks-9935160370

प्रियंका त्रिपाठी

नई दिल्ली

विधिक सलाहकार

lqjs'k ukjk;.k feJ

क्षेत्रीय सम्पादक

lkjHk dqekj] fcgkj

eks-09386075289

मो० अरशद

C;qjks phQ

eÅ

सोनी सब के 'पुष्पा इम्प सिबल' में आया नया मोड़, कादम्बरी ने अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा से सबको चौंकाया

मुंबई। सोनी सब का लोकप्रिय शो 'पुष्पा इम्प सिबल' अपनी प्रेरणादायक कहानी और भावनाओं से भरे किरदारों के साथ लगातार दर्शकों के दिल जीत रहा है। वकील बनने का सपना पूरा करने के लिए जुटी पुष्पा (करुणा पांडे) नए–नए इम्तिहानों का सामना कर रही है, जो न सिर्फ उसकी जिद और हिम्मत को परखते हैं बल्कि उसके रिश्तों को भी। हाल ही के एपिसोड्स में बापोदरा चाल जन्माष्टमी के उत्सव में डूबा था, लेकिन सबकी निगाहें पुष्पा और कादम्बरी (बृंदा त्रिवेदी) पर टिकी थीं। उत्सव के बीच कादम्बरी ने पुष्पा को मटका फोड़ प्रतियोगिता की खुली चुनौती दी। ड्रामा तब और गहराया जब पुष्पा ने पूरी हिम्मत और जज्बे के साथ कदम्बरी का सामना किया और जीत हासिल की। इसके बाद कादम्बरी को अपने वादे पर चलते हुए चाल छोड़ने की तैयारी करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही चाल ने चैन की साँस ली, कादम्बरी ने अचानक बेहोश होकर सभी को चौंका दिया और ऐलान किया कि वह प्रेग्नेंट है!

क्या यह चाल में रहने की उसकी नई साजिश है या उसके दावे में कोई सच्चाई है? पुष्पा अब एक नए तूफान में फँस गई है। क्या वह कदम्बरी की सच्चाई का पर्दाफाश कर पाएगी या इस तूफान में और उलझ जाएगी? कादम्बरी का किरदार निभा रहीं बृंदा त्रिवेदी ने बताया, "कादम्बरी बेहद परतों से भरी और अनपेक्षित है। उसकी हर हरकत चाल वालों को बेचैन रखती है और यही उसे निभाने को इतना दिलचस्प बनाता है। जब सबको लगता है कि कादम्बरी हार गई है और अब चाल से बाहर जाएगी, तभी वह एक बड़ा झटका देती है और प्रेग्नेंसी की घोषणा कर सबको हैरान कर देती है। एक अभिनेत्री के तौर पर मेरे लिए यह मजेदार है कि मैं ऐसे किरदार को निभा रही हूँ, जो हमेशा हालात को अपने पक्ष में मोड़ लेती है। यह नया ट्रैक कहानी में अप्रत्याशित ड्रामा जोड़ता है और मैं उत्साहित हूँ कि दर्शक देखेंगे कि पुष्पा इस घोषणा का सामना कैसे करती है।" देखना न भूलें 'पुष्पा इम्प सिबल', हर सोमवार से शनिवार रात ९रू३० बजे, केवल सोनी सब पर

गोविंदा और सुनीता, तलाक की अफवाहों को किया खारिज

मुम्बई। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें कुछ समय से चल रही थीं। लेकिन, गणेश चतुर्थी पर दोनों ने अपने बेटे यशवर्धन के साथ मिलकर

इस अफवाह को गलत साबित कर दिया। तलाक की खबरों का खंडन करते हुए सुनीता ने कहा, 'अगर कुछ हुआ होता, तो आज हम इतने करीब नहीं होते। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है। जब तक हम कुछ न कहें, कृपया इस बारे में कुछ न बोलें।' उन्होंने यह भी बताया कि गोविंदा के करियर की शुरुआत से ही उनके घर में गणपति की स्थापना की परंपरा रही है।

फिल्म उद्योग की हड़ताल के कारण रवि तेजा की मास जथारा की रिलीज टली

मुम्बई। फिल्म उद्योग की हड़ताल के कारण जाने–माने फिल्म अभिनेता रवि तेजा और अदाकारा श्रीलीला अभिनीत तेलुगु फिल्म मास जथारा २७ अगस्त को रिलीज नहीं होगी। इसके निर्माताओं ने मंगलवार को यह जानकारी दी। प्रोडक्शन हाउस 'सितारा एंटरटेनमेंट्स' ने अपने 'एक्स' हैंडल पर कहा कि हाल में फिल्म उद्योग की हड़ताल और महत्वपूर्ण विषय–वस्तु को पूरा करने में अप्रत्याशित देरी के कारण, 'मास जथारा' अपनी निर्धारित तिथि २७ अगस्त को प्रदर्शित नहीं हो पाएगी। उसने कहा कि इस फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज करने के लिए टीम तेजी से काम कर रही है तथा फिल्म को रिलीज करने की नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। 'तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री

एम्पलाइज फेडरेशन' ने कर्मचारियों के वेतन में ३० फीसदी वृद्धि की पुरानी मांग को लेकर चार अगस्त को हड़ताल का आह्वान किया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के हस्तक्षेप के बाद १८ दिन बाद हड़ताल समाप्त हुई। अनजान लोगों के लिए, मास जथारा, जिसे भानु बोगवारापु द्वारा निर्देशित किया गया है, में रवि तेजा के साथ अभिनेत्री श्रीलीला मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी विधु अयन्ना द्वारा की गई है जबकि संपादन नवीन नूली द्वारा किया गया है। सीथारा एंटरटेनमेंट्स और फ र्चयून फोर सिनेमाज के बैनर तले नागा वामसी एस और साई सौजन्या द्वारा निर्मित, यह फिल्म श्रीकारा स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत की जा रही है और मूल रूप से इस साल २७ अगस्त को स्क्रीन पर रिलीज होने वाली थी।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।

आर.एन.आई UPHIN/2010/32566

सम्पादक

आरती पाण्डेय

मो.9415087228

9889745884. 9807059191. 9026560178

Email- adbhutsamachar@yahoo.in adbhut_samachar@rediffmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक